P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-1* ISSUE-12* March- 2017
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

ग्रामीण विकास के मुद्दें एवं स्मार्ट गांवों की अवधारणा (राजस्थान के विशेष संदर्भ में)

रवीन्द्र मोदी
शोध छात्र,
भूगोल विभाग,
कोटा विश्वविद्यालय,
कोटा

हमीद अहमद
विभागाध्यक्ष ,
भूगोल विभाग,
राजकीय महाविद्यालय,
झालावाड़

सारांश

ग्रामीण जीवन की विशेषताओं का वर्णन करते हुए यह कहा जा सकता है, कि ग्रामीण जीवन में प्राकृतिक पर्यावरण होता है, यहाँ कृषि, पशुपालन एवं प्राथमिक कियाकलापों की प्रधानता रहती है। जनसंख्या का घनत्व कम रहता है, सामाजिक भावना पाई जाती है। लोग आस पड़ौसी से भावात्मक रुप से जुड़े होते हैं। जिससे अध्ययन किये गये गांवों में कई विविधतायें एवं समस्याये सामने देखने को मिली जो एक **'स्मार्ट गांव'** की अवधारणा में एक रुकावट बन सकती है, ये प्रमुख चुनौतियाँ है, जिसका सामना करना जरुरी हैं।

इस समस्याओं में गांवों में शहरों का गंदा पानी, कच्ची सड़के, परिवहन एवं जन–प्रवाह की समस्या, शुद्ध जल की समस्या, बिजली आपूर्ति की समस्या, मनोरंजन केन्द्रों की कमी, कूड़ा निस्तारण की समस्या, शौचालय का समस्या, छोटे–छोटे छप्पर युक्त मकान, टीन शेड, शिक्षा, की समस्या, रोजगार की समस्या, तकनीकी ज्ञान की कमी, इंटरनेट व ई–शिक्षा, की कमी, सरकारी योजनाओं से दूर आदि विशाल समस्याऐं राजस्थान के गांवों में पाई जाने की आम समस्या है, क्योंकि यहाँ के गांव अनियोजित तरीके से बने हैं। जिसके प्रभाव से **'स्मार्ट गांव'** का सपना धूमिल जैसा प्रतीत होता हैं।

अतः इन समस्याओं का निस्तारण तभी हो सकता है, जब इसका उचित उपाय कर जन– भागीदारी से अपनी–अपनी जिम्मेदारियाँ समझ कर **'स्मार्ट गांव'** का सपना पूरा किया जाये। इस हेतू गांवों में विकास तो हो किन्तु एक नियोजित तरीके से नियंत्रित रुप से हो, जिससे एक सभ्य गांव की स्थापना हो सकें क्योंकि भारत एक ग्रामीण समाज हैं। इस हेतू एक विकसित गांव की अवधारणा में पुरुष ही नहीं जबकि महिलाओं की भी विशेष भूमिका अदा करने की विशेष आवश्यकता हैं। अतः मानव अपने आस–पास के वातावरण का स्वयं की जिम्मेदारी मानकर बखूबी निभाये तो एक सभ्य गांव की संकल्पना की जा सकती है। इससे गांव विकसित एवं स्मार्ट बनेगा। इसके लिए सरकार भी विभिन्न गांवों को उपलब्ध व नई तकनीक की सहायता से स्मार्ट बनाने का प्रयत्न कर रही हैं। इन विभिन्न योजनाओं के द्वारा राजस्थान को एक 'स्मार्ट गांव' के रुप में परिवर्तित कर विकसित किया जा रहा है। किन्तु फिर भी राजस्थान जैसे राज्य के लिए यह एक चुनौतियों से भरा कार्य है, जहाँ का 60 प्रतिशत भाग रेगिस्तान से युक्त है, जहाँ मुख्य समस्या शुद्ध जल एवं बिजली आपुर्ति की है। इसके अलावा देश में कई पुराने बसे गांव भी है, जो अनियोजित तरीके से व अनियंत्रित रुप से बने है जहाँ पर हमेशा परिवहन, वायु, जल, कचरा निस्तारण, तंग गली, सीवरेज की समस्या, झुलते तार, गंदगी, गंदा पानी, टूटी–फूटी सड़के, सड़को का शहरों तक जुड़ाव न होना,चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार जैसी समस्या बड़ी मात्रा में फैली हैं। इसके अलावा राजस्थान के गांवो में लिंगानुपात की विविधता, महिलाओं में भेद, जाति भेद एवं कई कुरुतियाँ, जनसंख्या का ज्यादा बसाव, अशिक्षा, भाग्यवादिता, धार्मिक जुड़ाव, जीवन की गुणवत्ता का कम होना आदि भी विद्यमान है। एक आदर्श ग्राम बनाने के लिए मिशन के रुप में कार्य करना आवश्यक है, जिसमें स्वच्छता, पर्याप्त प्रकाश, आम बैठक का स्थान, जन सुनवाई, चौपालो का आयोजन एवं गांवों से प्राप्त कृषि फसलों को सही उपज प्राप्त कर उचित मूल्य प्राप्त हों, पशुओं से प्राप्त दुग्ध का डेयरी उपयोग हो, सिंचाई के लिए पर्याप्त जल एवं विद्युत मिले, स्कूलों को स्मार्ट बनाकर डिजिटल व रोजगार परक शिक्षा, दी जाये।

अतः इनको बढ़ावा देने के लिये मुख्य सेवा प्रदाताओं को आमंत्रित किया जाये ताकि धन निवेश में सहायता करें तथा परिचालन लागत से धन की वसूली कर सकें। लोगों को सूचनाएं प्रदान करने का बेहतरीन प्रबंधन, नागरीकों की भागीदारी, शिकायतों का ऑनलाइन निपटारा और सेवाओं की इलेक्ट्रानिक डिलीवरी, अपशिष्ट जल का सौ–फीसदी प्रशोधन, पेय जल की क्वालिटी की निगरानी, ऊर्जा के अक्षय स्रोत, स्मार्ट पार्किंग, यातायात प्रबंधन की बेहतर प्रणाली इत्यादि जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुये कार्य किया जाये तो 'स्मार्ट गांव' की संकल्पना की जा सकती है। इसके अलावा गांवों को शुद्ध वातावरण प्रदान हो इसलिए पर्यावरण कार्यक्रमों, वृक्षारोपण आदि जागरुकता कार्यक्रम चलाये जाये।

मुख्य शब्द : जन–प्रवाह, इंटरनेट, प्राकृतिक पर्यावरण, ग्रामीण विकास

प्रस्तावना

इस लघु शोध–पत्र में राजस्थान के विशेष संदर्भ में ग्रामीण विकास के मुद्दें, चुनौतियाँ स्मार्ट गाँवों की अवधारणा एवं समस्याओं के मूलभूत उत्तरदायी कारकों व उसको प्रभावित करने वाले प्रमाणों का अध्ययन किया गया हैं।

परिचय/अर्थ

अंग्रेंजी भाषा के 'रुरल' (RURAL) शब्द का हिन्दी रुपान्तरण 'इकाई' या 'ग्राम' है। गाँव को परिभाषित करते हुए यह कहाँ जा सकता है, कि यह एक ऐसा स्थान होता है जहाँ लोग साधारण जीवन जीते है, जहाँ लोग छोटे समुह में निवास करते है, जहाँ सुविधाओं का अभाव होता है किन्तु वातावरण शुद्ध, स्वच्छ एवं अच्छा होता हैं, उसे गाँव कहा जा सकता हैं। अधिकांश ग्रामवासी किसान होते हैं। कठोर परिश्रम, सरल स्वभाव और उदार ह्रदय उनकी विशेषताएं हैं। सुबह जब किसान अपने खेतों में हल चलाता है, तो पक्षी उसके बैलों की गति के साथ श्रम की महिमा का संगीत छेड़ देते हैं। किसान स्वभाव से निश्छल होते हैं। सबके पेट भरकर और तन ढककर भी स्वयं रुखा सूखा खा लेते है। गाँव की प्राकृतिक छटा मन मोह लेती है। दूर–दूर तक लहलहाते हुए हरे–भरे खेत और चारों तरफ रंग–बिरंगे फूल और उनकी फैली हुयी खुशबु मदहोश कर देती है। चारों तरफ चहचहाते हुए पक्षी मनमोह लेते हैं। ग्रामीण जीवन की विशेषताओं का वर्णन करते हुए यह कहा जा सकता है, कि ग्रामीण जीवन में प्राकृतिक पर्यावरण होता है, यहाँ कृषि, पशुपालन एवं प्राथमिक कियाकलापों की प्रधानता रहती है। जनसंख्या का घनत्व कम रहता है, सामाजिक भावना पाई जाती है। लोग आस पड़ोसी से भावात्मक रुप से जुड़े होते हैं।

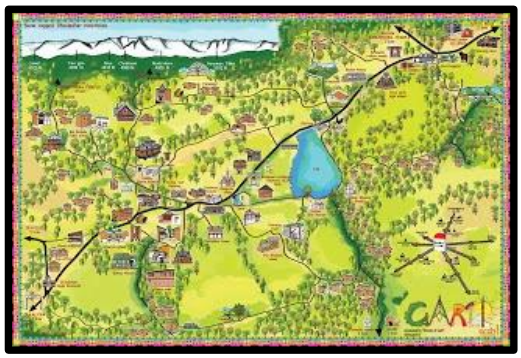

शोध का उद्देश्य

इस लघु शोध–पत्र का मुख्य उद्देश्य निम्न हैं –

1. राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न समस्याओं का आकलन।
2. राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों उत्पन्न पर्यावरणीय चुनौतियों का विहंगावलोकन करना।
3. पर्यावरणीय चुनौतियों के समुचित समाधान हेतु उपाय।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेतु उपाय।
5. स्मार्ट गाँव की योजना प्रस्तुत करना।

शोध विधि

प्रस्तुत शोध पत्र में गाँवों को विकसित तरीके से **'स्मार्ट गांव'** में परिवर्तित करना है। किन्तु इस बीच आऐ पर्यावरणीय, सामाजिक, आर्थिक चुनौती एवं उत्तरदायित्व व जिम्मेदारियो के विशेष संदर्भ में राजस्थान के विभिन्न गांवों में मेरे द्वारा स्वयं जाकर निरीक्षण किया गया जहाँ का भौगोलिक स्वरुप का तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति के आधार पर प्रारुप प्रयुक्त किया गया। अन्य सर्वेक्षण पद्वतियों का प्रयोग कर इस अध्ययन को अधिक विश्लेषणात्मक एवं वैज्ञानिक बनाया गया। इस लघु शोध अध्ययन में प्राथमिक व द्वितीय आंकड़ों (विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं) की सहायता से अन्वेषित किया गया। इसमें प्राथमिक आंकड़ों को यथायोग्य विधियाँ साक्षात्कार, प्रश्नावली, अनुसूची आदि द्वारा एकत्रित किए गये तथा द्वितीय आंकड़ों को लघु शोध में प्रकाशित एवं अप्रकाशित स्रोतो, सरकारी कार्यालयों एवं अपेक्षित विभागों में जाकर एकत्रित किये गये एवं उनका विस्तृत अध्ययन कर आधारभूत सांख्यिकी विधियों के द्वारा विश्लेषित व संश्लेषित किया गया जिससे अध्ययन किये गये गांवों में कई विविधतायें एवं समस्याये सामने देखने को मिली जो एक **'स्मार्ट गांव'** की अवधारणा में एक रुकावट बन सकती है, ये प्रमुख चुनौतियाँ है, जिसका सामना करना जरुरी हैं।

अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत शोध अध्ययन का क्षेत्र राजस्थन राज्य है, जो हमारे भारत देश के उत्तरी–पश्चिमी भाग में स्थित एक अनुपम प्रान्त है। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान 23^0 3' से 30^0 12' उत्तरी अक्षांश तथा 69^0 30' से 78^0 17' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित हैं। 23^0) उत्तरी अक्षांश रेखा (कर्क रेखा) राजस्थान राज्य में बांसवाड़ा–डूँगरपुर जिलों से होकर गुजरती हैं। राज्य के उत्तर में पंजाब, दक्षिण में मध्यप्रदेश एवं गुजरात, पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में मध्यप्रदेश एवं उत्तरप्रदेश हैं। उत्तरी–पूर्व में हरियाणा व देहली राज्य हैं, तथा दक्षिण पूर्व में मध्यप्रदेश है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र का अधिकांश भाग 3,36,808 वर्ग किलोमीटर व शहरी क्षेत्र 5,431 वर्ग किलोमीटर आता हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का भारत में पहला स्थान हैं। इसकी उत्तर से दक्षिण की लम्बाई 826 किलोमीटर व पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर तक फैली है। राज्य के पश्चिम में मरुस्थल, मध्य में लम्बवत् समानांतर अरावली की पर्वत श्रेणियां, दक्षिण पूर्व में हाड़ौती का पठार, पूर्व में बेसिन हैं। राज्य का अधिकांश भाग मरुस्थलीय हैं। यहाँ का धरातलीय स्वरुप उबड़–खाबड़, पथरीला है, जिसका अधिकांश भाग प्राचीनतम आग्नेय चट्टानों से बना है। जलवायु की दृष्टि से इसका अधिकांश भाग उपोष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। विशेषतः इसका पश्चिमी भाग शुष्क जलवायु का, मध्य–पश्चिमी भाग एवं मध्य–पूर्वी भाग अर्द्र–शुष्क जलवायु एवं पूर्वी–दक्षिणी, पूर्वी भाग में नम जलवायु पाई जाती है। राज्य की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 68621012 थी जिसमें पुरुषों की जनसंख्या 35620086 एवं स्त्री जनसंख्या 33000926 थी। लिंगानुपात 926 रही। घनत्व की बात करे तो 201

व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर एवं साक्षरता दर 67.06 प्रतिशत रही। प्राकृतिक दृष्टि से राज्य का 61 प्रतिशत भू– भाग मरुस्थलीय है। राज्य में मिश्रित पतझड़ वन, काटेदार झाड़ियां, शुष्क वन, शुष्क सागवान वन, अर्द्र उष्ण सदाबहार वन आदि पाये जाते हैं।

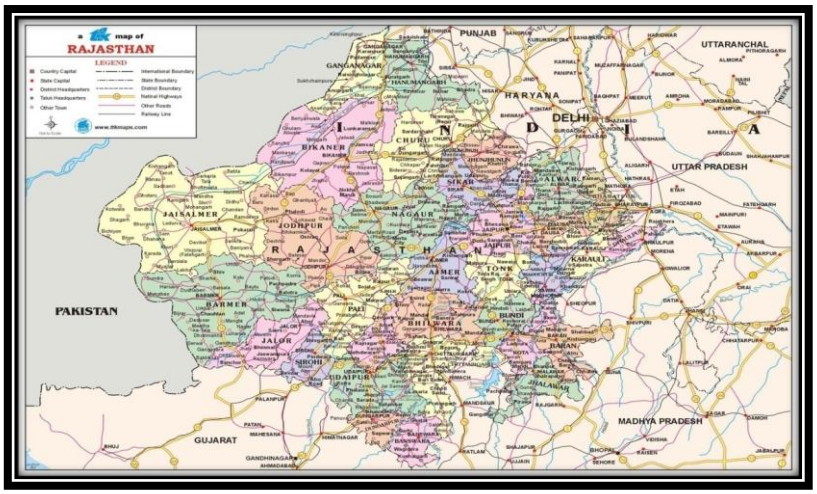

स्मार्ट (SMART) का अर्थ

S	Social, Skilled and Simple	Zero Tolerance for Caste and Creed or better no caste & creed and no discrimination on Gender and Religion Everyone is Literate and skilled Simple living and high thinking.
M	Moral, Methodical and Modern	Moral values of Gandhiji, Swami Vivekananda etc Methodical using Total Literacy and latest techniques Modern like cities.
A	Aware, Adaptive and Adjusting	Highest level of awareness on global social & economic issues Adaptive and adjusting to fast changing environments.
R	Responsive and Ready	Responsive to collective wisdom, cooperative movement & larger social issues Ready to generate own resources for self-sufficiency and self-reliance.
T	Techno-Savvy and Transparent	Techno-savvy for IT and Mobile usage Transparent in harmonic relations and delivery of services.

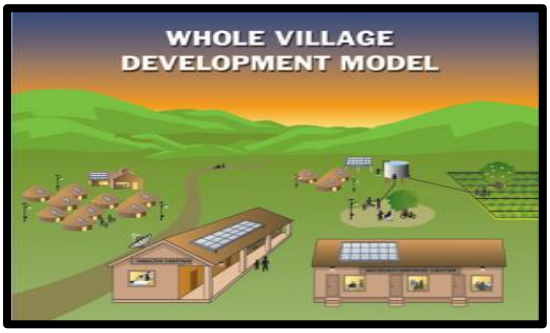

ग्रामीण विकास की समस्यायें

राजस्थान के विशेष अध्ययन कर पाया गया की यहाँ के गाँवों में कई ऐसी समस्यायें है, जिस कारण **'स्मार्ट गांव'** की अवधारणा में रुकावटें उत्पन्न कर सकती है, इन समस्याओं में गांवों में शहरों का गंदा पानी, कच्ची सड़के, परिवहन एवं जन–प्रवाह की समस्या, शुद्ध जल की समस्या, बिजली आपूर्ति की समस्या, मनोरंजन केन्द्रों की कमी, कूड़ा निस्तारण की समस्या, शौचालय का समस्या, छोटे–छोटे छप्पर युक्त मकान, टीन शेड, शिक्षा, की समस्या, रोजगार की समस्या, तकनीकी ज्ञान की कमी, इंटरनेट व ई–शिक्षा की कमी, सरकारी योजनाओं से दूर आदि विशाल समस्याऐं राजस्थान के गांवों में पाई जाने की आम समस्या है, क्योंकि यहाँ के गांव अनियोजित तरीके से बने हैं। इस कारण ही भारतवर्ष उस गति से तरक्की नहीं कर पा रहा जिस गति से उसे करनी चाहिए। एक सौं इक्कीस करोड़ लोगों के देश में लगभग 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। और यह आबादी अधिकांश रुप से गाँवों में ही निवास करती हैं। जिसके प्रभाव से **'स्मार्ट गांव'** का सपना धुमिल जैसा प्रतीत होता हैं।

अतः इन समस्याओं का निस्तारण तभी हो सकता है, जब इसका उचित उपाय कर जन– भागीदारी से अपनी–अपनी जिम्मेदारीयाँ समझ कर **'स्मार्ट गांव'** का सपना पूरा किया जाये।

इस हेतु गांवों में विकास तो हो किन्तु एक नियोजित तरीके से नियंत्रित रुप से हो, जिससे एक सभ्य गांव की स्थापना हो सकें क्योंकि भारत एक ग्रामीण समाज हैं। भारत की आत्मा गाँवों में रहती हैं। सन् 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत के शहरों में मात्र 31.16% आबादी ही निवास करती है, इसके विपरित ग्रामीण क्षेत्रों में भारत की 68.84% आबादी निवास करती है। सांख्यिकी विभाग राजस्थान के सन् 2011 के आकड़ों के अनुसार बात करे तो यहाँ कुल कस्बे सहित 44795 गाँव, एवं कस्बे को छोड़कर 44672 गाँव रहा, जो एक बहुत बड़ी मात्रा में हैं। इतनी बड़ी मात्रा में भारत में ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या निवास करती है। इस हेतु एक विकसित गांव की अवधारणा में पुरुष ही नहीं जबकी महिलाओं की भी विशेष भूमिका अदा करने की विशेष आवश्यकता हैं। अतः मानव अपने आस–पास के वातावरण का स्वयं की जिम्मेदारी मानकर बखुबही निभाये तोएक सभ्य गांव की संकल्पना की जा सकती है। इससे गांव विकसित एवं स्मार्ट बनेगा। इसके लिए सरकार भी विभिन्न गांवों को उपलब्ध व नई तकनीक की सहायता से स्मार्ट बनाने का प्रयत्न कर रही हैं। जिससे वे ज्यादा कुशलता के साथ अलग–अलग लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें। भारत सरकार की एक अच्छी पहल **'स्मार्ट सिटी'** के बाद अब **'स्मार्ट गांव'** की रुपरेखा तैयार की जा रही है। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा कई योजनायें चलाई जा रही जिसे निम्न बिन्दुओं के माध्यम से समझा जा सकता है–

1. **सांसद आदर्श ग्राम योजना**
   इस योजना का प्रारम्भ 11 अक्टूबर 2014 को हुआ। इसके अंतर्गत प्रत्येक सांसद 2019 तक 3 गांवों को गोद लेकर उसे विकसित करे तथा 2016 तक अपने संसदीय क्षेत्र में एक मॉडल गाँव तैयार करना।
2. **दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना** इस योजना के अंतर्गत गांवों में अबाध बिजली आपूर्ति का लक्ष्य पूरा करना है। यह योजना राजीव गांधी ग्रामीण विधुतिकरण योजना का परिवर्तित रुप हैं।
3. **पण्डित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना**
   इस योजना का प्रारम्भ 17 जुलाई 2014 में हुआ। यह देश का सबसे बड़ा स्कील ट्रेनिंग प्रोग्राम है। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय व राजस्थान सरकार का संयुक्त तत्वावधान हैं।

इन विभिन्न योजनाओं के द्वारा राजस्थान को एक 'स्मार्ट गांव' के रुप में परिवर्तित कर विकसित किया जा रहा है। **'स्मार्ट गांवों'** के रुप में ऐसे गाँव बनाना निश्चित रुप से सरकार द्वारा घोषित एक महान कार्यक्रम हैं। किन्तु फिर भी राजस्थान जैसे राज्य के लिए यह एक चुनौतियों से भरा कार्य है, जहाँ का 60 प्रतिशत भाग रेगिस्तान से युक्त है, जहाँ मुख्य समस्या शुद्व जल एवं बिजली आपुर्ति की है। जहाँ पर पूरे देश की अधिकांश आबादी निवास करती है। इसके अलावा देश में कई पुराने बसे गांव भी है, जो अनियोजित तरीके से व अनियंत्रित रुप से बने है जहाँ पर हमेशा परिवहन, वायु, जल, कचरा निस्तारण, तंग गली, सिवरेज की समस्या,

झूलते तार, गंदगी, गंदा पानी, टुटी–फुटी सड़के, सड़को का शहरों तक जुड़ाव न होना, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार जैसी समस्या बड़ी मात्रा में फैली हैं। इसके अलावा राजस्थान के गांवो में लिंगानुपात की विविधता, महिलाओं में भेद, जाति भेद एवं कई कुरुतियाँ, जनसंख्या का ज्यादा बसाव,, भाग्यवादीता, धार्मिक जुड़ाव, जीवन की गुणवत्ता का कम होना आदि भी विद्यमान है। इस हेतु राजस्थान में आधुनिक गांवो की आर्थिक बढ़त, उच्च जीवन स्तर व पर्यावरणीय धारणीयता के गढ़ के रुप में निर्मित करना होगा।

अतः राजस्थान जैसे राज्य में इतनी बड़े स्तर की योजना को पूरा करने के लिए सही व बड़े स्तर की भागीदारी की आवश्यकता हैं। इस हेतु लोगों को अपने आस–पास के वातावरण को शुद्ध, साफ–सुथरा रखे, घरेलू अपशिष्टों को यथा स्थान डाले। स्मार्ट पारिस्थिति–तंत्र बनाने के लिए मुख्य हितधारियों का विश्वास जीतना आवश्यक हैं। किसी भी संबंधित मुद्दे पर सरकारी एजेंसियों, राजनीतिक पार्टीयों, ग्रामीण संस्थाओं की आम राय होना आवश्यक हैं।

एक आदर्श ग्राम बनाने के लिए मिशन के रुप में कार्य करना आवश्यक है, जिसमें स्वच्छता, पर्याप्त प्रकाश, आम बैठक का स्थान, जन सुनवाई, चौपालो का आयोजन एवं गांवों से प्राप्त कृषि फसलों को सही उपज प्राप्त कर उचित मूल्य प्राप्त हों, पशुओं से प्राप्त दुग्ध का डेयरी उपयोग हो, सिंचाई के लिए प्रर्याप्त जल एवं विधुत मिले, स्कूलों को स्मार्ट बनाकर डिजिटल व रोजगार परक शिक्षा, दी जाये। जिसे निम्न बिन्दुओं के माध्यम से गांवों में ये सुविधाएं मुहैया की जाये तो गांवों को **'स्मार्ट रुप'** में देखा जा सकता है।

स्मार्ट गांव की अवधारणा के लिए किये जा सकने वाले प्रयास :–

1. गांवों में निः शुल्क शिक्षा प्रदान कर साक्षरता दर में सुधार करना।
2. रोजगार प्रशिक्षण देकर अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों की स्थिति में सुधार किया जाये।
3. कृषि उत्पाद, टैक्टर, खाद, उर्वरक, औजार आदि आसानी से मुहैया करवाया जाये।
4. फसल बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष में उत्पादित फसलों का बीमा किया जाये, जिससे किसान आर्थिक संकट से बच सके।
5. अनिवार्य शिक्षा कानून लागू किया जाये।
6. गांवों को ई–गर्वनेंस, ई–शिक्षा से जोड़ा जाये हर घर में शौचालय का निर्माण किया जाये।
7. गांवों को सड़क व संचार माध्यम से शहरों से जोड़ा जाये।
8. स्वास्थ बीमा कार्ड, टीकाकरण, समय–समय पर मेडिकल जाँचें की जाये।
9. मोबाईल व इंटरनेट के माध्यम से गांवों को जोड़ा जाये।
10. टी.वी. व संचार माध्यम से कृषि सम्बन्धित जानकारी किसानों को समय–समय पर दी जानी चाहिये।
11. स्वच्छ व साफ पानी की आपूर्ति की जाये।
12. स्वच्छ पक्की सड़के बनवाई जाये।
13. अबाध बिजली आपूर्ति की जाये।
14. स्कूलों को डिजिटल बनाया जाये।
15. ग्रामीण प्रशासन के कार्यो को ऑन–लाईन किया जाये।
16. किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए देखभाल की उचित व्यवस्था की जाये।
17. आगनबाड़ीयों के माध्यम से गांवों की महिलाओं की देख भाल की जाये।
18. 10 किलोमीटर के क्षेत्र में व्यावसायिक संस्था हो।
19. ई–लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाये।
20. मनोरंजन, वयस्कों और बच्चों के लिये खेल मैदाल की उचित व्यवस्था की जाये।
21. गांवों में थियेटर, स्कूल व सार्वजनिक हॉल हो।
22. सरकारी डेयरी हो।
23. 5 किलोमीटर के क्षेत्र में गांवों में बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाईयाँ उपलब्ध हो।
24. महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाये।
25. बेरोजगारों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाये।
26. कौशल विकास योजना को बढ़ावा दिया जाये।
27. सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाये।
28. राजस्थान के गांवों में आंध्रप्रदेश के नेल्लोर जिले के पुत्तम, राजूवरी, केदरिगा में उपलब्ध ई–टॉयलेट जैसी स्तर की सुविधा प्रदान की जाये।
29. स्कूलों में मिड–डे–मील को बढ़ावा दिया जाये।
30. इग्नू विश्वविद्यालय द्वारा की गई पहल को गांवों में संचालित कर योजनाओं का लाभ उठाया जाये।
31. धूल मुक्त गलियाँ व सड़के हो।
32. सभी के घरों में पूजा का स्थल हो।
33. स्वास्थ्य जांच और उपचार के लिए उचित साधन उपलब्ध हो।
34. 10 किलोमीटर के एक क्षेत्र के भीतर मल्टी सुविधा अस्पताल हो।
35. विवादों को निपटाने के लिए पंचायत सशक्त हो।
36. मल–मूत्र निकासी के लिए एक निश्चित स्थान की उपलब्धता हो।
37. आम बैठक की उचित जगह हो।

अतः इनको बढ़ावा देने के लिये मुख्य सेवा

प्रदाताओं को आमंत्रित किया जाये ताकि धन निवेश में सहायता करें तथा परिचालन लागत से धन की वसूली कर सकें। लोगों को सूचनाएं प्रदान करने का बेहतरीन प्रबंधन, नागरीकों की भागीदारी, शिकायतों का ऑनलाइन निपटारा और सेवाओं की इलेक्ट्रानिक डिलीवरी, अपशिष्ट

जल का सौ–फीसदी प्रशोधन, पेय जल की क्वालिटी की निगरानी, ऊर्जा के अक्षय स्त्रोत, स्मार्ट पार्किंग, यातायत प्रबंधन की बेहतर प्रणाली इत्यादि जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुये कार्य किया जाये तो 'स्मार्ट गांव' की संकल्पना की जा सकती है। इसके अलावा गांवों को शुद्ध वातावरण प्रदान हो इसलिए पर्यावरण कार्यक्रमों, वृक्षारोपण, आदि जागरुकता कार्यक्रम चलाये जाये।

निष्कर्ष

'स्मार्ट गांव' बनाने की परिकल्पना पूरे देश विशेषतः राजस्थान राज्य के परिदृष्य में निश्चित रुप से पूरी हो सकती है बशर्ते इसकों राष्ट्रीय व राज्य परिस्थितियों और शहर आधारित जरुरतों के अनुरुप लागू किया जाए। इसके साथ–साथ, भविष्य में विकास एवं प्रबंधों के लिए कुछ नमूने आदर्श सिद्ध होने चाहिए, जिससे गांवों में वृद्धि के साथ गांवों का विकास भी हो एवं गांवों का वातावरण शुद्ध, स्वच्छ व हो जिससे लोगों का दम ना घुटे एवं स्वच्छ व स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *शर्मा., एम. एल., एवं शर्मा एच.एस., राजस्थान का भूगोल, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 2012*
2. *भूगोल ओर आप आइरिस पब्लिकेशन प्रा. लि, नई दिल्ली.*
3. *RNP Sinha, Geography and Rural Development, Concept Publishing Company, 1992*
4. *Bharat Grameen Vikas Report 2013-14.*
5. *जोशी, आर. "पर्यावरण भूगोल", साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा, 2002.*
6. *rajcensus.gov.in*